

राजनीतिक स्वार्थ एवं अवसरवादिता

एटमी करार के बहाने वामपंथी दलों द्वारा केन्द्र की सरकार से समर्थन वापस लेने के साथ ही राजनीतिक अवसरवादिता का दृश्य भारत के राजनीतिक वातावरण में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में 'संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन' की सरकार पिछले 4वर्षों से केन्द्र में शासन कर रही है जिसे वामपंथी दल बाहर से समर्थन दे रहे थे। यद्यपि प्रारम्भ से ही यूसरकार हर .ए.पी. मोर्चे पर विफल साबित हुई। बावजूद इसके वामपंथी दलों द्वारा भी लगातार इन सब की अनदेखी की जा रही थी। आज देश की आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति अत्यन्त ही खतरनाक है तो महँगाई चरम पर होने के कारण आम नागरिक तबाह हो गया है। इस सब के लिये कांग्रेस नेतृत्व की यूसरकार की नीतियाँ जहाँ .ए.पी. जिम्मेदार रही हैं वहीं इस सरकार को आँखें मूँदकर समर्थन कर रहे वामपंथी बराबर के जिम्मेदार हैं। आज चुनाव की आहट सुनकर वामपंथी एटमी करार का बहाना बनाकर अपने दाग को धोने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं तो कांग्रेस तथा उसके सहयोगी गठबन्धन के दलों को देश के सम्मान और सम्प्रभुता की तुलना में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छवि की चिन्ता ज्यादा सता रही है। वामपंथियों के समर्थन वापसी से केन्द्र में अस्थिरता का वातावरण बना है। इसके साथ ही राजनीतिक अवसरवादिता का दृश्य भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वामपंथी दल आज जिस एटमी करार का विरोध कर रहे हैं उसके पीछे उनकी राष्ट्रनिष्ठा नहीं अपितु चीन के प्रति निष्ठा ही छिपी है। यह एक वामपंथी नेता ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि "अगर भारत और अमेरिका के बीच एटमी करार होगा तो इसका चीन के हितों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। यह है भारत के वामपंथियों की राष्ट्रनिष्ठा। " संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन से वामपंथियों की समर्थन वापसी के बाद समाजवादी पार्टी ने केन्द्र सरकार को समर्थन की घोषणा कर दी। सपा द्वारा केन्द्र सरकार को समर्थन पहली बार नहीं दिया गया। इससे पूर्व मई, में कांग्रेस गठबन्धन की 2004

सरकार बनाते समय बिना बुलाये सपा भी उस बैठक में शामिल हो गई थी जिसे कांग्रेस ने कोई महत्त्व नहीं दिया। इससे अपमानित होने के बावजूद दो वर्षों तक सपा द्वारा केन्द्र सरकार को समर्थन दिया गया। बाद के दिनों में सपा की प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेतृत्व की केन्द्र सरकार में तनाव के कारण सपा द्वारा केन्द्र से और कांग्रेस द्वारा प्रदेश से समर्थन वापस लिया गया था। आज सपा द्वारा केन्द्र सरकार को एटमी करार के बहाने समर्थन पुनः देने का कारण डॉ .जे.पी.ए . अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति की राय का कारण बताया जाना अत्यन्त ही कलाम की राय को महत्त्व देती है .हास्यास्पद है। क्या सचमुच सपा डॉ? डॉ . कलाम ने तो सम्पूर्ण देश के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने की वकालत भी की थी। डॉकलाम पूरे भारत के लिये जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी नीति बनाने के भी पक्षधर हैं। क्या सपा डॉकलाम के इस राय से भी सहमत है अथवा अपने वजूद को बचाने की कवायद में सपा ने यह राह पकड़ी है? क्या यह सच नहीं कि आय से अधिक सम्पत्ति रखने के मामले में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को फँसते देख सपा ने अपना रुख बदला है? उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बसपा तो एटमी करार पर देश के अनुकूल अथवा प्रतिकूल तर्क देने के बजाय इसे 'मुस्लिम विरोधी' करार देकर राष्ट्र की तुलना में अपने वोट बैंक की ज्यादा चिन्ता का उदाहरण दे चुकी है। राजनीतिक अवसरवादिता के ढेर सारे उदाहरण वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। इससे न इस राष्ट्र का कल्याण होने वाला है और न ही समाज का। एटमी करार के नाम पर कांग्रेस, सपा, बसपा अथवा वामपंथी सभी देश की जनता की आँखों में धूल झाँकने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी विफलता को छुपाने के लिए जहाँ कांग्रेस तथा वामपंथी इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाये हैं तो अन्य कथित सेकुलर दल इसे राजनीतिक लाभ एवं हानि से जोड़कर देख रहे हैं। देश की जनता स्वार्थी एवं अवसरवादी दलों से सजग हो, यही वर्तमान की माँग एवं राष्ट्र की आवश्यकता है।